not there in the roadmap of the Railway? Is the Government showing any kind of apathy or step-motherly attitude towards the State of Kerala?

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I would like to draw the attention of the hon. Member to the fact that this question doesn't belong to each and every State of India. There are 29 States in the Union of India and there are also Union Territories. This is about passenger services on newly-constructed broad gauge lines. What we have given here is that these are the other gauge lines converted to broad gauge lines and these are the trains started on them. As far as Kerala is concerned, probably the hon. Member was not present in the House when I gave the entire figure of how much money has been given to Kerala, which is more than any time in the past. Sir, we have also entered into an agreement with the Kerala Government to make a joint venture, and this is in addition to the amount of money that has already been given to the Kerala Government by the normal budgetary resources, which is far more than any time in the past. Also, incidentally, we started Humsafar Train from Kerala. Probably, you are not keeping track about what new trains are being started. Probably, you are more in Delhi. But I am saying that we have started a lot of trains in Kerala also. I have personally gone there and flagged off the train. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: Sir, hon. Minister is misleading the House. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No discussion on this. ...(*Interruptions*)... Mr. Ragesh ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: Sir, hon. Minister is misleading the House. ...(*Interruptions*)... Not a single train is started in Kerala. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The question is not on that. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: Sir, he is misleading the House. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The question is not on that. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: Sir, he is misleading and that is why I have to intervene. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please Question No. 379.

Funds for upliftment of farmers in Punjab

*379. SHRI SHWAIT MALIK: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has sanctioned any funds for upliftment of farmers in Punjab; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Details showing release under the schemes implemented by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare and Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries to the State of Punjab are given in the Statement given below:–

(₹ in crore) Year 2016-17

Sl.No.	Name of the Scheme	Releare
1.	Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)	95.81
2.	Sub-mission on Agriculture Mechanization (SMAM)	52.09
3.	National Horticulture Mission (NHM)	30.00
4.	National Food Security Mission (NFSM)	9.85
5.	Support to State Extension Programme for Extension Reforms. Now, Sub-mission on Agriculture Extension (SMAE)	9.00
6.	Sub-Mission on Agroforestry (SMAF)*	2.00
7.	(i) National Mission on Micro Irrigation (NMMI). On Farm Water Management (OFWM). Now, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) [For Micro Irrigation]	1.18
	(ii) Ministry of Water Resource component are for two projects in Punjab#	52.42
8.	Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics	2.33
9.	Livestock Health and Disease Control CASP	10.70
10.	National Livestock Mission	3.43
11.	Inland Fisheries	9.99
12.	National Mission On Bovine Productivity	1.00
13.	State Disaster Response Fund (SDRF)	306.75
	TOTAL	586.55

* SMAF Scheme being implemented since 2016-17.

For Kandi canal-Extn. Ph-II and rehabilitation of first Patiala and Kota Branch.

श्री श्वेत मलिकः ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो कृषि है, उसका सारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। पंजाब का किसान सारे देश का पेट भरता है, लेकिन उन्हें विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है क्योंकि यह बॉर्डर स्टेट है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2016-17 में पंजाब के किसानों के upliftment के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या contribution है? ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेशः सर, यह बार-बार जुगलबंदी क्या हो रही है?

MR. CHAIRMAN: Please; what is wrong with that?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, पंजाब में हमारी कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और 2016-17 में हमने कितनी धनराशि दी है, यह सब हमने सभा पटल पर भी रखा है और माननीय सदस्य को भी बताया है। इसके अलावा जो राज्य आपदा अनुक्रिया कोष है या फिर 14वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है, उसमें भी बहुत बड़ी राशि पंजाब के लिए बढ़ायी गयी है।

श्री श्वेत मलिकः सर, जो फसल बीमा योजना है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बहुत बढ़िया योजना चलायी गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पंजाब में उसके संबंध में जानकारी लेना चाहूंगा।

श्री राधा मोहन सिंहः सर, पंजाब में फसल बीमा योजना वहां की सरकार ने लागू नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि जो नयी सरकार आयी है, वह उसे वहां जरूर लागू करेगी।

श्री शमशेर सिंह ढुलोः धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके मार्फ त माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन पंजाब में किसानों द्वारा खुदकुशियां दिन-पर-दिन बढ़ रही हैं। यहां पर उनके welfare के लिए जो फंड रखा गया है, वह बहुत कम है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो farmer होता है, एक तो land owner होता है और एक tenant होता है। पिछली दफा भी माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया था, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि एक तो वे farmer की परिभाषा बताएं, क्योंकि कई दफा जो tenants हैं या जो landless labourers हैं, वे भी किसानी के साथ जुड़े होते हैं। क्या उनके welfare के लिए भी आपने कुछ प्रावधान किया है? पंजाब ने हमेशा central pool में अनाज का 60 परसेंट योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त diversification के लिए जो फंड रखा गया है, वह भी बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब के लिए आप फंड बढ़ाने का कोई प्रावधान करेंगे?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला)ः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पिछली बार सवाल पूछा था, वह मुझे याद है। आपने सवाल में पूछा था कि जो landless labors हैं, वे किसानी दूसरे landlord की करते हैं, तो क्या उनको फसल बीमा का बेनिफिट मिल सकता है? हां, उनको फसल बीमा का बेनिफिट मिल सकता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप जवाब सुन लीजिए।

श्री परषोत्तम रुपालाः उसको मिल सकता है। अपनी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में इसका प्रावधान है। यदि वह किसान के साथ अपना एमओयू करके प्रीमियम भरेगा, तो उसको

भी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का cover दिया जाएगा। चूंकि पंजाब में इसको लागू ही नहीं किया है, नई सरकार को नोटिफिकेशन करके इसको लागू करना होता है। अगर राज्य सरकार ऐसा करेगी, तो इसका बेनिफिट इनको भी मिलेगा।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, the question is regarding funds for upliftment of farmers in Punjab. I am afraid that the Ministry has, जैसे बोलते हैं कि पतीलों की खुरचन इकट्ठी करी है, यह जवाब में दिया है। The figures have been given. For National Mission on Bovine Productivity, Rs.1 crore has been allotted. For National Mission on Micro Irrigation, Rs.1.18 crore has been allotted. For Agroforestry, Rs.2 crore have been allotted. The answer is far from satisfactory. The coffers in Punjab are empty. The newly elected Chief Minister of Punjab recently visited Delhi and called on the Agriculture Minister and the Prime Minister asking for a special package for Punjab farmers, who have been compelled to commit suicide in large numbers in the last ten years. I want to know whether this Government is planning to consider that special package and how much they are planning to consider.

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, माननीय सदस्या जिस कम धनराशि की चर्चा कर रही हैं, यह तो राज्य का वर्ष 2016-17 का जो कुल आवंटन है, वह नहीं है, जो first किश्त रिलीज़ हुई है, वह है। आप देखेंगी, तो कई योजनाओं का भी, सिर्फ पंजाब सरकार का ही नहीं, अन्य सरकारों को भी पिछले वर्ष जो राशि गई, वह पूरी खर्च नहीं हो पाई। जो इस वर्ष की राशि गई, उसका भी first allotment हो गया, जब उसका UC आएगा, तब दूसरी किश्त उनको जाएगी। यह मात्र रिलीज है। मैं एक उदाहरण पंजाब का बताना चाहूंगा, जैसे उस राज्य में micro irrigation है, वर्ष 2015-16 में 42.99 करोड़ रुपये निर्गत किए गए, जिसमें से राज्य ने 9.45 करोड़ रुपये खर्च किए। ऐसा सिर्फ इसी राज्य ने नहीं किया है, बल्कि मैक्सिमम राज्यों की यही स्थिति है। आवंटन ज्यादा है और राज्य पहली किश्त खर्च करेंगे, तब दूसरी किश्त जाएगी। इसमें एक दिक्कत यह भी होती थी कि हमारे बजट के पास होने की जो प्रक्रिया होती थी, उसके बाद पैसा मई में राज्यों को जाता था और जून से वर्षा शुरू हो जाती थी। इसमें किसी राज्य का कसूर नहीं है। इसीलिए पहली बार, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार 31 मार्च के पहले सारी बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस बार अप्रैल के सेकंड वीक में ही राज्यों को पैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष से खर्चे की गति बढ़ेगी, पैसे की कोई कमी नहीं है, पहले खर्च नहीं हो पाता था।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, my specific question regarding special package for the upliftment of farmers, as sought by the Chief Minister of Punjab, has not been answered by the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: The Minister may reply - yes or no.

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, मैं फिर आपको बताऊंगा कि जब आपकी सरकार थी ...(**व्यवधान**)... मैं राज्य को विशेष सहायता देने की बात कर रहा हूं। वर्ष 2010 से 2015 तक उस राज्य को 21 हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दी गई थी। यह 2010 से 2015 तक की हिस्सेदारी है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, don't interrupt.

श्री राधा मोहन सिंहः और 2015 से यह राशि बढ़कर लगभग तीन गुणा हो गई है। इसको 63 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह भी राज्य को विशेष सहायता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः ठीक है, ठीक है। ...(**व्यवधान**)... Ambikaji, please, there is no need for further discussion.

श्री राधा मोहन सिहः मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। पांच वर्ष के अंदर उस राज्य को 21 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं और 2015 से 2020 तक 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

MR. CHAIRMAN: Let us take the next supplementary question. Mr. Tulsi.

SHRI K. T. S. TULSI: Sir, according to the statement which the hon. Minister has laid on the Table of the House, there are 13 schemes, in which moneys have been released and the total amount is ₹ 586.55 crore. My question to the hon. Minister is: Why is it that not even a rupee has been released with regard to the Prime Minister's Crop Insurance Scheme?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, फसल बीमा योजना के अंतर्गत नुकसान के आंकड़े आते हैं और तब भारत सरकार अपना अंश देती है, लेकिन पंजाब में यह बीमा योजना नहीं चल रही है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। अगर पंजाब में यह योजना चलती और फसल के नुकसान के आंकड़े आए होते, तो हमने कितनी राशि दी, इस का जिक्र होता।

SHRI K. T. S. TULSI: There is no reference to that. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंहः जब वहां योजना चल ही नहीं रही है, तो जिक्र कैसे होगा।

श्री जयराम रमेशः सर, लगता है, मंत्रालय के अंदर थोड़ा communication gap है।

MR. CHAIRMAN: All right. Let us move to the next question.

*380. **[The questioner was absent.]**

Revenue generation in railways

*380. SHRI ANUBHAV MOHANTY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways are planning to earn revenue from non-fare sources so that the passengers are not burdened by raising train fares;

(b) whether it is also a fact that Railways are planning to earn a revenue of about ₹ 2000 crore by way of offering branding packages of full trains; and

(c) whether only the products of the advertiser will be sold in the whole train or platform, leaving no choice to the public/passengers visiting the platform or travelling by the train?